प्रेषक,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उत्तरांचल–देहरादून।

प्रेष्य,

वरिष्ठ शोध अधिकारी,
नियोजन निदेशालय,
उत्तरांचल–देहरादून।

पत्रांकः /जि0यो0/विविध–2004 दिनांकः दिसम्बर 04 ,2004

विषयः– जिला योजना हेतु निर्धारित प्रारूपों में रोजगार सृजन सम्बन्धी प्रारूप को जोड़ने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन द्वारा दिनांकः 22 नवम्बर 2004 को रोजगार सृजन सम्बन्धी ली गई बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (कार्यवाही संलग्न)। उक्त बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा अपेक्षा की गई कि प्लॉन एवं नॉन प्लान से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं से प्राप्त रोजगार सृजन की समीक्षा नियमित रूप से की जाय। इस सम्बन्ध में दिनांकः 29.11.04 को अपर सचिव, नियोजन एवं निदेशक, अर्थ एवं संख्या द्वारा भी निदेशालय स्तर पर हुई अर्थ एवं संख्याधिकारियों की बैठक में इस बात पर बल दिया कि जिला योजना हेतु निर्धारित प्रारूपों में विभागीय योजनाओं से प्राप्त/ अपेक्षित रोजगार सृजन सम्बन्धी प्रारूप पृथक से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में बैठक में निम्न बिन्दुओं पर निर्णय लिया गया।

1– जिला योजना हेतु निर्धारित प्रारूपों में विभागीय योजनाओं से प्राप्त/अपेक्षित रोजगार सृजन सम्बन्धी प्रारूप पृथक से होना चाहिए ताकि राज्य में विभिन्न योजनाओं द्वारा उपलब्ध प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रोजगार की जानकारी हो सके। अतः रोजगार सम्बन्धी प्रारूप पृथक से होना चाहिए।

2– एन0आई0सी0 के अधिकारी श्री मनीष वालिया द्वारा अवगत कराया गया कि स्टेट बैव पर जिला योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों को एक मुश्त अवमुक्त धनराशि की स्थिति उपलब्ध है। यदि विभाग जनपदवार अवमुक्त धनराशि की फॉट एन0आई0सी0 को उपलब्ध करा दे तो जनपदवार फॉट की स्थिति भी स्टेट बैव पर उपलब्ध हो जायेगी।

3– जिला स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी नियुक्त हैं। अतः जिला योजना हेतु नोडल अधिकारी के रूप में अधीक्षण अभियन्ता को नामित किया जाय।

अपर सचिव, नियोजन द्वारा अपेक्षा की है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाय। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 मनोज कुमार पन्त)
उप निदेशक,
कृते निदेशक,
उत्तरांचल–देहरादून।

पत्रांकः 1974/ जि0यो0/विविध–2004 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–
(1) अपर सचिव, नियोजन, उत्तरांचल शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
(2) राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 उत्तरांचल।
(3) श्री ए0एस0 धौनी, शोध अधिकारी, नियोजन निदेशालय, उत्तरांचल–देहरादून।

उप निदेशक,
कृते निदेशक,
उत्तरांचल–देहरादन।

NIC 820

(8)

सचिव नियोजन ने अवगत कराया कि राज्य के मुख्य GDP ड्राइवर ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्यान तथा बायो टैक्नोलॉजी(जड़ी बूटी) प्रमुख हैं। इन विभागों में कितना तथा किस–किस स्तर का रोजगार सृजित हो सकता है की गहनतम समीक्षा आवश्यक हैं। उन्होंने यह भी बल दिया कि चूँकि राज्य में ऊर्जा में भविष्य में व्यापक सरकारी, गैर सरकारी स्तर पर राज्य विद्युत कार्पोरेशन तथा अन्य प्राइवेट कम्पनियों द्वारा विभिन्न तकनीकी तथा गैर तकनीकी रोजगार दिए जाने की सम्भावना है। अतः यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि राज्य के विभिन्न जनपदों में स्थित आई0टी0आई0 तथा पौलोटैक्निक के छात्रों को इन कारपोरेशन तथा प्राइवेट कम्पनियों द्वारा रोजगार देय हो सके। मुख्य सचिव ने उत्तरांचल विद्युत निगम में रोजगार सृजन के अवसरों को स्थिति की समीक्षा के निर्देश दिए। मुख्य सचिव द्वारा जल विद्युत परियोजना की स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में तीनों इन्जीनियरिंग कालेजों,पालिटेक्निकों व आई0टी0आई0 के विषयों को जल विद्युत परियोजनाओं से सृजित होने वाली रोजगार सम्भावनाओं के अनुकूल बनाने के अपने पूर्व निर्देशों में हो रहे विलम्ब पर खेद व्यक्त किया तथा इस पर शीघ्र अंतिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

(कार्यवाहीः सचिव ऊर्जा, सचिव नियोजन)

सचिव नियोजन ने उद्यान विभाग में रोजगार सृजन हेतु ढ़ॉचारोपण के कार्यों हेतु, वैज्ञानिक Skill प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण आयोजन किये जाने पर बल दिया जिससे यह भी सुनिश्चित हो सके कि ऐसे प्रशिक्षणों से ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार की सम्भावनायें प्राप्त हों।

(कार्यवाहीः सचिव कृषि एवं उद्यान)

इसी प्रकार मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी विभाग योजनावार कार्यक्रमों की समीक्षा कर रोजगार सृजन सम्बन्धी योजनाओं को Identified कर लें तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षों में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से उत्पन्न होने वाले रोजगार सृजन की स्थिति को स्पष्ट कर नियोजन विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाहीः समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव नियोजन)

अनुमोदित

(डा0 आर0 एस0 टोलिया)
मुख्य सचिव।

संख्याः 57 /3090-नि0/2004 दिनांकः ~~नवम्बर~~ दिसम्बर 02 ,2004

प्रतिलिपि– निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।

(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।

02/12/04
(एल0 फैनई)
अपर सचिव,
नियोजन।

041204002.pdf

सम्बन्धी बैठक का कार्यवृत्त।

स्थान:- मुख्य सचिव सभा कक्ष, सचिवालय परिसर। दिनांक:22 नवम्बर, 2004

दिनांक 19 नवम्बर 2004 को योजना आयोग भारत सरकार के साथ दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक समीक्षा के दौरान रोजगार सृजन की स्थिति तथा भावी रणनीति सम्बन्धी चर्चा का जिक्र करते करते हुए मुख्य सचिव द्वारा यह अपेक्षा की कि समस्त विभागों के प्लान, नान प्लान तथा बजट की रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों के सापेक्ष समीक्षा कर ली जाय। इस सम्बन्ध में यथा आवश्यक नियोजन विभाग द्वारा रोजगार सृजन सम्बन्धी सूचनाऐं लेने हेतु एक प्रारूप (Format) विकसित कर लिया जाय।

(कार्यवाहीः समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव नियोजन)

मुख्य सचिव ने अपर सचिव(कार्मिक) को निर्देश दिए कि वे समस्त विभागों के रिक्त पदों की स्थिति प्राप्त करे लें, तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से अब तक रिक्तियों को भरे जाने हेतु पदोन्नति तथा नियुक्तियों की क्या स्थिति है, तथा योजना के अन्तिम दो वर्षों हेतु विभागवार नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों हेतु क्या रणनीति अपनाई जा रही है।

मुख्य सचिव ने प्रदेश में रोजगार सृजन की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अपर सचिव कार्मिक को तीन प्रकार की सूचनाऐं प्राप्त करने के निर्देश दिए।

1. सभी विभागों में लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने वाले पदों की स्थिति तथा रिक्त पदों का विवरण।
2. लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के पदों की स्थिति एवं रिक्त पदों का विवरण।
3. विभिन्न योजनाओं यथा आंगनबाड़ी, ग्राम प्रहरी, स्वंय सेवी संस्थाओं के माध्यम, सहकारिता आदि द्वारा प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से दिए जा रहे रोजगार की स्थिति।

समस्त सचिव उक्तानुसार अपने विभागों की समीक्षा कर लें तथा कार्मिक एवं नियोजन विभाग को पन्द्रह दिन में अवगत करायेंगे।रिक्त पदों को भरने, आरक्षित पदो के न भरने की दशा में विशेष भर्ती अभियान का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अनुश्रवण किया जायेगा।

(कार्यवाहीः समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, प्रमुख सचिव कार्मिक, सचिव नियोजन)

रोजगार सृजन की स्थिति की समीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य सचिव ने सचिव नियोजन को निर्देश दिए कि प्रतिदिन 3–4 विभागों को बुलाकर उनके प्लान तथा नान प्लान योजनाओं की समीक्षा कर ली जाय तथा सभी विभागों की योजनाओं में यह देख लिया जाय की किन–किन योजनाओं से कितना रोजगार सृजन हो रहा है एवं किन योजनाओं में रोजगार सृजित करने का Potential है तथा कितनी योजनाओं में दूरगामी रोजगार प्राप्त हो सकते हैं? इसके अतिरिक्त विभागों को योजना संरचना में यह स्पष्ट निर्देश दे दिये जांय कि वही नई योजनाऐं Takeup की जाय जिनमें रोजगार सृजन की सम्भावना हों। अतः इस हेतु आवश्यकतानुसार सम्बन्धित योजनाओं के परिव्यय को भी बढा दिया जाय। प्रत्येक विभाग चालू विभिन्न विकास योजनाओं को इस प्रकार Dovetail भी करने पर विचार करें जिससे रोजगार के अवसर स्पष्ट रूप से सृजित हो। मुख्य सचिव स्तर पर नियोजन विभाग साप्ताहिक समीक्षा करायेंगे जिसमें विभागवार प्रगति समीक्षा की जायेगी।